



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 7 फरवरी, 2024

माघ 18, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 13/ग्यारह-2-24-9(47)-17-टी0सी0 250-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (311)-2024

लखनऊ, 7 फरवरी, 2024

अधिसूचना

प0आ0-35

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 20 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 445/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (118)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 और अधिसूचना संख्या 496/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (186)-2021, दिनांक 28 जून, 2021 तथा अधिसूचना संख्या 596/ग्यारह-2-22-9(47)-17टी0सी0 187-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (252)-2022, दिनांक 21 जुलाई, 2022 और अधिसूचना संख्या 515/ग्यारह-2-23-9(47)-17टी0सी0215-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (273)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 का आंशिक उपांतर करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा नीचे यथा विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित, उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन, संदत्त किए गए या कम संदत्त किए गए कर या गलत प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए, आदेश जारी करने की, धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार करती हैं, अर्थात् :-

(एक) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 30 अप्रैल, 2024 तक;

(दो) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 31 अगस्त, 2024 तक।

आज्ञा से,

नितिन रमेश गोकर्ण,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 13 / XI-2-24-9(47)-17-T.C.250-U.P.Act-1-2017-Order (311)-2024, dated February 7, 2024 :

No. 13 / XI-2-24-9(47)-17-T.C.250-U.P.Act-1-2017-Order (311)-2024

Dated Lucknow, February 7, 2024

In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the "said Act") read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 13 of 2017) and in partial modification of the notification no. 445 / XI-2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(118)-2020, dated May 11, 2020 and no. 496/XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order (186)-2021, dated June 28, 2021 and no. 596 / XI-2-22-9(47)-17 T.C. 187-U.P.Act-1-2017-Order (252)-2022, dated July 21, 2022 and no. 515 / XI-2-23-9(47)-17 T.C.215-U.P.Act-1-2017-Order (273)-2023, dated April 24, 2023, the Governor on the recommendations of the Council, hereby, extends the time limit specified under sub-section (10) of section 73 for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilised, relating to the period as specified below, namely :-

- (i) for the financial year 2018-19, up to the 30th day of April, 2024;
- (ii) for the financial year 2019-20, up to the 31st day of August, 2024.

By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1109 राजपत्र-2024-(3101)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 44 सा० राज्य कर-2024-(3102)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।